THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): (a) IMF has aproved an extended arrangement authorising purchases upto the equivalent of SDR 5 billion for the next 3 years.

(b) Yes; Sir.

(c) The Government do not agree with the reasons indicated by the U.S. Executive Director while abstaining, namely, that India's proposal did not adequately show a balance of payments need. The Government of India had made known to the Fund the deterioration in India's balance of payments position due, among other reasons, to increase in oil prices and the Fund Management had accepted India's balance of payments need.

राजस्थान के जालौर जिले में पाए गए खनिजों से प्राप्त राजस्व की राशि

1031. **श्री विरदा राम फूलवारिया :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जालौर जिले में पाए गए खनिजों से अब तक सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; तथा वित्तीय वर्ष 1981-82 में कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है; और

(ख) क्या सरकार इस क्षेत्र में खनिजों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रही है और यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार जालौर जिले में पाए गए खनिजों से प्राप्त राजस्व राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	राजस्व राशि
1974–75 से 1980–81	10,81,681.00 रुपये
1981–82 (अनुमानित)	3,50,000.00 रुपये

(ख) जी हां । राजस्थान सरकार का खान विभाग प्रत्येक वर्ष खनिजों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण और खोज कर रहा है । 1980-81 वर्ष में 100 वर्ग किलोमीटर लक्ष्य की तुलना में 306 वर्ग किलोमीटर में टोही सर्वेक्षण किया गया । इसी प्रकार क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रण के अंतर्गत 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर काम किया गया है । 1981-82 वर्ष में राजस्थान के खान विभाग ने टोही सर्वे के अंतर्गत 250 वर्ग किलोमीटर का लक्ष्य रखा है इसके अलावा फ्लोराइट की खोज हेतु 300 मीटर डिलिंग का लक्ष्य रखा गया है । गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि के बारे में बताना अभी संभव नहीं है ।

Backlog in recruitment and Promotion of S.C. and S.T. Employees in LIC

1032. SHRI M. ARUNACHALAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is a backlog in the matter of recruitment and promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees of nearly 12,408 posts as on 31st March, 1980 in all the cadres of employees in LIC of India;

(b) if so, what special measures to remove this backlog have been taken by the LIC of India at par with other public sector institutions (i.e. Bank of India, Air India, RBI etc.); and